



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 795) पटना, मंगलवार, 30 सितम्बर 2014

सं0 08/आरोप-01-100/2014,सां0प्र0-9554

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

14 जुलाई 2014

श्री रमेश मिश्र, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज के विरुद्ध किशनगंज जिला में चाय की खेती मात्र के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री मिश्र द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1697/रा० दिनांक 22.11.1995 को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 17 आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए अनुशंसा की गयी। जबकि सरकारी भूमि के आवंटन के लिए राजस्व विभाग का उपरोक्त पत्रांक-1997/रा० दिनांक 22.11.1995 मात्र इकाईयों/प्लान्ट की स्थापना के लिए था, न कि चाय की खेती के लिए।

2. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री मिश्र से विभागीय ज्ञापांक 3929 दिनांक 02.05.2006 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई तथा श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक 9080 दिनांक 11.09.2006 द्वारा मंतव्य की माँग की गई। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636 दिनांक 28.08.2009 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त आरोपों

की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10670 दिनांक 29.10.2009 द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक 16646 दिनांक 22.10.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री मिश्र द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त श्री मिश्र के विरुद्ध किशनगंज जिला में चाय की खेती के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाये गये।

5. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 18619 दिनांक 06.12.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गई। आयोग के पत्रांक 167 दिनांक 25.04.2014 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई।

अतः श्री रमेश मिश्र (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज सम्प्रति अपर समाहर्ता वैशाली को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 (ix) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है—

1. अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेजा दी जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 795-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>